GEO IAS
It's about quality

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Daily News Analysis

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Tuesday, 18 March, 2025

Edition : International Table of Contents

Page 01 **Syllabus : GS 3 : Indian Economy**	सोने और कच्चे तेल के आयात में गिरावट के बाद भारत का माल व्यापार घाटा 42 महीने के निचले स्तर पर
Page 06 **Syllabus : GS 2: Indian Polity**	कैग नियुक्ति प्रक्रिया पर याचिका की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट
Page 07 **Syllabus : GS 3 : Enviroment and Ecology**	भारत के गेहूं उत्पादन चक्र पर जलवायु परिवर्तन का क्या असर हो रहा है?
Page 10 **Syllabus : GS 2 : Indian Polity**	चुनावी सुधार क्यों जरूरी हैं?
Page 12 **Syllabus : GS 3 : Indian Economy**	निर्मित वस्तुओं के कारण फरवरी में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 2.38% पर पहुंच गई
Page 08 : Editorial Analysis: **Syllabus : GS 1 : Indian and World Geography**	एक ऐसा देश जहां महत्वाकांक्षा बिना किसी आउटबाउंड टिकट के बढ़ती है

GEO IAS It's about quality

Page 01 : GS 3 : Indian Economy

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, सोने, चांदी और कच्चे तेल के आयात में गिरावट के कारण फरवरी 2025 में भारत का माल व्यापार घाटा 42 महीने के निचले स्तर 14.05 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है।

- जनवरी 2025 में 22.9 बिलियन डॉलर और फरवरी 2024 में 19.5 बिलियन डॉलर की तुलना में यह उल्लेखनीय कमी दर्शाता है।

India's goods trade deficit at 42-month low following dip in gold, crude imports

Ashokamithran T.
MUMBAI

India's goods trade deficit was down to a 42-month low of $14.05 billion as imports of gold, silver and crude dipped in February, show data from the Commerce and Industries Ministry.

The difference between import and export of goods was $22.9 billion in January. In February 2024, the merchandise trade deficit stood at $19.5 billion.

India's gold and silver imports were at $2.7 billion, which is the lowest since June 2024, when the value was $2.5 billion.

As for crude and petroleum, imports were at $11.89 billion, which was the lowest since July 2023, when the value was at $11.81 billion.

India exported goods worth $36.9 billion in February 2025. Imports, however, slipped to a 22-month low of $50.9 billion.

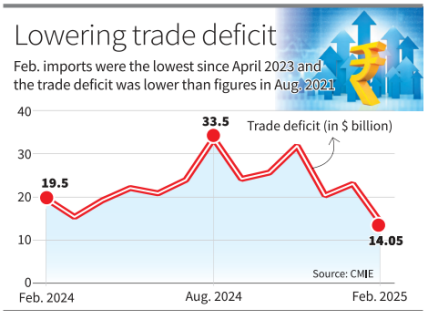

On a year-on-year basis, exports dipped 10.84% in February 2025.

Leap year effect

"A portion of the YoY decline in merchandise exports can be attributed to the base year effect related to the leap month," Aditi Nayar, chief economist at the credit rating agency ICRA, wrote in a statement.

Imports however shrunk 16.3% in the reporting month as against the corresponding period last year.

"The trade deficit was significantly lower than the average of over $23 billion during the first 10 months of FY2025," Ms. Nayar said.

"Given this, we now expect the current account to witness a surplus of around $5 billion in Q4 of FY2025, equivalent to around 0.5% of the GDP, in the ongoing quarter."

(With inputs from Reuters)

मुख्य बातें

1. व्यापार घाटे के रुझान

- फरवरी **2025: $14.05** बिलियन (**42** महीने का सबसे निचला स्तर)।
- जनवरी **2025: $22.9** बिलियन।
- फरवरी **2024: $19.5** बिलियन।
- औसत व्यापार घाटा (अप्रैल **2024 -** जनवरी **2025): $23** बिलियन से अधिक।

2. आयात में गिरावट

- सोना और चांदी का आयात: **$2.7** बिलियन (जून **2024** के बाद सबसे कम - **$2.5** बिलियन)।
- कच्चा और पेट्रोलियम आयात: **$11.89** बिलियन (जुलाई **2023** के बाद सबसे कम - **$11.81** बिलियन)।
- कुल आयात: **$50.9** बिलियन (**22** महीने का सबसे निचला स्तर)।
- आयात में साल-दर-साल गिरावट: **16.3** प्रतिशत।

3. **निर्यात प्रदर्शन**

- फरवरी **2025** में निर्यात: **$36.9** बिलियन।
- निर्यात में साल-दर-साल गिरावट: **10.84** प्रतिशत।

4. **लीप वर्ष का प्रभाव**

- लीप वर्ष प्रभाव (फरवरी **2024** में एक अतिरिक्त दिन) ने साल-दर-साल तुलना को प्रभावित किया है, जैसा कि आईसीआरए की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने बताया है।

5. **चालू खाता अधिशेष अनुमान**

- वित्त वर्ष **2025** की चौथी तिमाही में चालू खाते में कम व्यापार घाटे के कारण लगभग **5** बिलियन डॉलर (जीडीपी का **0.5** प्रतिशत) का अधिशेष देखने को मिलने की उम्मीद है।

व्यापार घाटे में कमी के पीछे कारण

1. **कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट**

- वैश्विक कच्चे तेल की कम कीमतों ने भारत के कच्चे तेल के आयात बिल को कम कर दिया है, जिससे व्यापार घाटे पर दबाव कम हुआ है।

2. **सोने और चांदी की कम मांग**

- उच्च घरेलू कीमतों और आयात शुल्क जैसी सरकारी नीतियों के कारण मांग में कमी।

3. **सुस्त वैश्विक मांग**

- वैश्विक आर्थिक मंदी भारतीय वस्तुओं की निर्यात मांग को प्रभावित कर रही है।

4. **नीतिगत उपाय**

- भारत सरकार ने निर्यात विविधीकरण और आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा दिया है, जिससे आयात नियंत्रित हुआ है।

भारत की अर्थव्यवस्था के लिए निहितार्थ

1. **चालू खाता शेष पर सकारात्मक प्रभाव**

- कम व्यापार घाटा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और मुद्रा स्थिरता पर दबाव कम करता है।

2. **मुद्रास्फीति प्रभाव**

- कम कच्चे तेल का आयात उद्योगों में इनपुट लागत को कम करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है।

3. **निर्यात वृद्धि में चुनौतियाँ**

- निर्यात में **10.84** प्रतिशत की गिरावट वैश्विक व्यापार में मंदी का संकेत देती है, जिसका असर भारत के औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्रों पर पड़ रहा है।

4. **मौद्रिक और राजकोषीय नीतिगत विचार**

- भारतीय रिजर्व बैंक व्यापार और पूंजी प्रवाह के रुझानों पर विचार करते हुए मौद्रिक नीतियों को समायोजित कर सकता है।

निष्कर्ष

- भारत के व्यापार घाटे में **42** महीने के निचले स्तर पर गिरावट अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक विकास है। हालांकि, निर्यात में गिरावट वैश्विक मांग संबंधी चिंताओं का संकेत देती है। सरकार और नीति निर्माताओं को दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए टिकाऊ आयात नीतियों को बनाए रखते हुए विविधीकरण, मुक्त व्यापार समझौतों और बुनियादी ढांचे में सुधार के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: भारत के व्यापार घाटे में हाल ही में आई गिरावट में योगदान देने वाले कारकों की जाँच करें। निर्यात वृद्धि सुनिश्चित करते हुए भारत इस प्रवृत्ति को कैसे बनाए रख सकता है? (250 words)

सर्वोच्च न्यायालय भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की वर्तमान प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार के नियंत्रण में है।

- याचिका में तर्क दिया गया है कि यह प्रणाली CAG की स्वतंत्रता से समझौता करती है, जो केंद्र और राज्य सरकारों की वित्तीय निगरानी के लिए जिम्मेदार एक संवैधानिक प्राधिकरण है।

SC to examine petition on CAG appointment process

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The Supreme Court on Monday decided to examine a plea challenging the sole prerogative of the Centre, acting through the President, to appoint the Comptroller and Auditor General of India.

Appearing before a Bench headed by Justice Surya Kant, advocate Prashant Bhushan said absolute control by the Centre over the appointment process of a Comptroller and Auditor General (CAG) would gravely affect the independence of a Constitutional authority, which was a watchdog over the financial expenditure and accountability of the Union and State governments and even the Panchayati Raj institutions.

The petition said the CAG must be appointed by the President in consultation with a non-partisan selection committee comprising the Prime Minister, the Leader of the Opposition and the Chief Justice of India.

The petitioner, Centre for Public Interest Litigation, also represented by advocate Cheryl D'Souza, referred to recent "deviations" in the CAG's work, including reports on the "pause" in Maharashtra audits, a steady decline on audits on the Union government, among others.

Mr. Bhushan said Article 148(1) of the Constitution equates the CAG with a Supreme Court judge. A CAG can be removed only for the same reasons and in the same manner as an apex court judge.

Issuing notice to the Union government, Justice Kant, however, asked whether a judicial intervention would amount to re-writing Article 148, which deals with the appointment of a CAG. Article 148, like in the case of Supreme Court judges, is silent about the procedure of appointment. Justice Kant also remarked that one should be able to "trust institutions".

Mr. Bhushan argued that giving exclusive control to the Executive over appointments to key Constitutional bodies would be a sure recipe for loss of independence.

याचिका में उठाए गए प्रमुख मुद्दे

- **पारदर्शी चयन प्रक्रिया का अभाव**

  o सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा दायर याचिका में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सदस्यता वाली एक गैर-पक्षपाती चयन समिति के गठन की मांग की गई है।

  o इससे निष्पक्ष और स्वतंत्र नियुक्ति प्रक्रिया सुनिश्चित होगी, जिससे कार्यपालिका का नियंत्रण कम होगा।

- CAG **की भूमिका और स्वतंत्रता**

  o **CAG** वित्तीय जवाबदेही का प्रहरी है और पंचायती राज संस्थाओं सहित सरकारी व्यय का लेखा-जोखा रखता है।

  o इसकी नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालिका का पूर्ण नियंत्रण संभावित पक्षपात और सरकारी वित्त की कम जांच पर चिंता पैदा करता है।

- **कानूनी और संवैधानिक दृष्टिकोण**

  o संविधान के अनुच्छेद **148(1)** में राष्ट्रपति द्वारा **CAG** की नियुक्ति का प्रावधान है, लेकिन इसमें प्रक्रिया निर्दिष्ट नहीं की गई है।

  o **CAG** को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही है, जो कार्यकाल की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। हालांकि, उचित नियुक्ति तंत्र की कमी इसकी कार्यात्मक स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती है।

- **न्यायिक हस्तक्षेप और शक्तियों का पृथक्करण**

  o सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल उठाया कि क्या नियुक्ति प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना अनुच्छेद **148** को फिर से लिखने के समान होगा।

  o न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने संस्थाओं पर भरोसा करने की आवश्यकता पर बल दिया, उन्होंने सुझाव दिया कि नियुक्तियों में न्यायिक हस्तक्षेप पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

CAG **के काम में हाल ही में हुए विचलन पर चिंताएँ**

केंद्र सरकार के ऑडिट में गिरावट

- याचिका में केंद्र सरकार के व्यय की ऑडिट जांच में कमी का उल्लेख है।

महाराष्ट्र ऑडिट में "विराम"

- राज्य वित्तीय ऑडिट की पारदर्शिता को प्रभावित करने वाले राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप।
- ये चिंताएँ सीएजी के कामकाज में अधिक स्वतंत्रता और जवाबदेही की आवश्यकता को उजागर करती हैं।

भारतीय राजनीति और शासन के लिए निहितार्थ

संस्थागत स्वायत्तता को मजबूत करना

- यदि सर्वोच्च न्यायालय चयन समिति को अनिवार्य बनाता है, तो इससे कार्यकारी प्रभुत्व कम होगा और सीएजी रिपोर्ट की विश्वसनीयता बढ़ेगी।
- **न्यायिक अतिक्रमण बनाम संस्थागत विश्वास**

  o यह मामला एक संवैधानिक दुविधा को जन्म देता है - क्या न्यायपालिका को कार्यकारी नियुक्तियों में हस्तक्षेप करना चाहिए या स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत सुरक्षा उपायों पर निर्भर रहना चाहिए।

- **वित्तीय निरीक्षण पर प्रभाव**

  o अधिक स्वतंत्र **CAG** सार्वजनिक व्यय में पारदर्शिता में सुधार कर सकता है और सरकारी वित्तीय प्रबंधन में भ्रष्टाचार को कम कर सकता है।

- **अन्य संवैधानिक नियुक्तियों के लिए मिसाल**

  o यह मामला चुनाव आयोग और केंद्रीय सतर्कता आयोग जैसे अन्य संवैधानिक निकायों की नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।

निष्कर्ष

- **CAG** नियुक्ति प्रक्रिया की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच एक महत्वपूर्ण संवैधानिक घटनाक्रम है। नियुक्तियों में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने से संस्थाओं में जनता का विश्वास बढ़ सकता है और वित्तीय जवाबदेही में सुधार हो सकता है। इस मामले का परिणाम अन्य संवैधानिक प्राधिकरणों की नियुक्ति प्रक्रियाओं में सुधारों के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: शासन में वित्तीय जवाबदेही बनाए रखने के लिए संवैधानिक निकायों की स्वतंत्रता आवश्यक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा करें। (250 words)

गेहूं भारत में चावल के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा खपत वाली मुख्य फ़सल है, जिसे मुख्य रूप से सिंधु-गंगा के मैदानों में उगाया जाता है। हालाँकि, जलवायु परिवर्तन, विशेष रूप से बढ़ते तापमान और मानसून के पैटर्न में बदलाव, इसके उत्पादन चक्र को बाधित कर रहे हैं।

How climate change is affecting India's wheat production cycle

The Indian Ocean is warming at an accelerated rate, which in turn is affecting India's monsoon, on which most of the country's agriculture depends. The kharif or summer crop season is starting and ending late, which delays the beginning of the rabi season. And wheat is a rabi crop

Priyali Prakash

India recorded its warmest February in 124 years this year. The India Meteorological Department has already raised an alarm for March, saying that the month will experience above normal temperatures and more than the usual number of days with heat waves. The period coincides with the beginning of India's wheat harvest season, and extreme heat poses a grave threat for the country's second-most consumed crop, after rice.

Wheat in India

In India, wheat is primarily grown in the northwestern parts of the Indo-Gangetic plains. Primary producers include the states of Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, and Madhya Pradesh. Wheat needs a cooler season to grow, and the crop is usually sown between October and December. It is harvested between February and April in the rabi crop season.

The Indian government set a wheat procurement target of 30 million tonnes for the 2025-2026 rabi marketing season, news agency PTI reported in January. The lower procurement target comes despite the agriculture ministry aiming for a record wheat production of 115 million tonnes in the 2024-2025 crop year (July-June), the report added.

In 2024-2025, government wheat procurement was recorded at 26.6 million tonnes. While this exceeded the 26.2 million tonnes procured in 2023-2024, it fell short of the 34.15 million tonne target for the year.

In May 2022, India had prohibited wheat exports. This was shortly after Russia invaded Ukraine, a major wheat-producing country, which disrupted international availability of the food grain and triggered a global price hike.

Heat and wheat

Climate variability itself is not a new phenomenon, but it catches our attention when the crop growth season overlaps with heat wave conditions, Sandeep Mahato of the M.S. Swaminathan Research Foundation (MSSRF), Chennai, told *The Hindu*.

A 2022 study in the *International Journal of Molecular Sciences* noted that increasing global warming is causing heat stress that "triggers significant changes in the biological and developmental process of wheat, leading to a reduction in grain production and grain quality."

According to the paper's authors, heat stress is known to affect the growth and development of wheat by altering "physio-bio-chemical processes such as photosynthesis, respiration, oxidative damage, activity of stress-induced hormones, proteins and anti-oxidative enzymes, water and nutrient relations, and yield-forming attributes (biomass, tiller count, grain number, and size) upon exposure to temperatures above the optimum range,"

Stages of wheat growth

According to the UN Food and Agriculture Organisation, stages of wheat growth are defined based on how different organs of the plant develop. This can be broadly grouped into four stages:

(i) Germination to emergence: This includes the growth of the seed until the seedling breaks through the soil surface and the first leaf emerges.

(ii) Growth stage 1: Steps from emergence to double ridge. Shoots appear, and the plant growth shifts focus from producing primordial leaves to flowering structures called spikelets.

(iii) Growth stage 2: This stage lasts from double ridge to anthesis. This is where the focus of the plant shifts from the vegetative to the reproductive stage. This is also one of the stages where the plant is comparatively more susceptible to heat stress.

(iv) Growth stage 3: This stage includes the grain-filling period, from anthesis to maturity.

According to experts, the real problem starts with the oceans. The Indian Ocean is warming at an accelerated rate. A 2024 study conducted by scientists at the Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune, noted that the water body will likely be in a "near-permanent heat wave state" mainly as a result of global warming by the end of the century.

The frequency of marine heat waves is expected to increase tenfold, from the current average of 20 days per year to 220-250 days per year, the study added.

A warming Indian Ocean will in turn alter India's monsoon, on which most of the country's agriculture depends. For example, the kharif or summer crop season is starting and ending late, which inevitably delays the beginning of the rabi season.

Wheat is a rabi crop. If its sowing starts late, the later stages of plant growth will coincide with early heat waves in India. February 2025 was warmer than usual, and similar trends have been predicted for March. This is also the peak season for wheat harvest, and the ideal temperature in the later stages of the plant's growth should not cross 30° C.

"High temperatures cause early flowering and faster ripening, shortening the grain-filling period. This results in lighter grains with lower starch accumulation, reducing the total wheat output," Prakash Jha, assistant professor of agricultural climatology at Mississippi State University, told *The Hindu*.

"Extreme heat causes wheat to develop higher protein content but lower starch, making the grain harder and affecting milling quality. Farmers may face lower market prices due to reduced grain weight and quality issues," he added.

Low crop yield also tends to make farmers desperate and result in overuse of fertilizers, fungicides, etc. Nikhil Goveas, lead climate advisor with the Environmental Defense Fund, told *The Hindu*. "Higher but inefficient use of resources is another cascading effect of heat-stress challenges in crops."

Adaptation and mitigation

Food security is central to the adaptation and mitigation strategies officials use to lower the heat stress on wheat crops.

"Wheat is ... important for farmers because it can be consumed immediately, so part of the produce is always saved for household consumption," Goveas said.

Farmers rely on older varieties of the crop because accessibility is a challenge, with problems related to the supply chain, costs, etc. Climate-resilient varieties are important, but they are not a silver bullet solution to the challenge, Goveas added, "The problem is a deeper challenge of the climate crisis on our food systems. The earth is getting warmer. We need to think about not just one crop but all crops: get timings right, have our information and weather systems updated with the knowledge of what to expect, and undertake mitigation efforts against the challenges."

"The larger question here is to be able to guarantee food security," Mahato of MSSRF Chennai said. "We have to focus on addressing yield gaps. This ties into the issue of management of resources like fertilizers, pest control, etc."

According to Mahato, immediate policy support to farmers to deal with heat stress effects on wheat can be in the form of compensation, but there are more long term solutions that need to be incorporated into our agricultural practices.

"Changes in agricultural management strategies to support early sowing of crops in areas that are likely to see early heat waves, or introducing improved yield varieties with shorter growth duration, are some policy changes that can alleviate heat stress on wheat," he added. "There is no compromise that can be done on improving production, and that should be the central goal to the adaptation question."

"Policymakers must take a multi-pronged approach, combining scientific research, financial support, technological solutions, and farmer education to protect wheat crops from rising heat stress," according to Jha. "This includes promoting heat-resistant wheat varieties, adjusting sowing dates, financial support and crop insurance, and weather monitoring and advisories."

priyali.prakash@thehindu.co.in

In India, wheat is primarily grown in the Indo-Gangetic plains. Producer states include Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, and Madhya Pradesh. ANI

Optimal temperature required for growing wheat

Stages	Optimum temperature	Minimum temperature	Maximum temperature
Seed germination	20-25 ± 1.2	3.5 - 5.5 ± 0.44	35 ± 1.02
Root growth	17.2 ± 0.87	3.5 ± 0.73	24.0 ± 1.21
Shoot growth	18.5 ± 1.90	4.5 ± 0.76	20.1 ± 0.64
Leaf initiation	20.5 ± 1.25	1.5 ± 0.52	23.5 ± 0.95
Terminal spikelet	16.0 ± 2.30	2.5 ± 0.49	20.0 ± 1.60
Anthesis	23.0 ± 1.75	10.0 ± 1.12	26.0 ± 1.01
Grain filling duration	26.0 ± 1.53	13.0 ± 1.45	30.0 ± 2.13

> Changes in strategies to support early sowing of crops in areas that are likely to see early heat waves, or introducing improved yield varieties with shorter growth duration, are some policy changes that can alleviate heat stress on wheat

- हिंद महासागर के तेजी से बढ़ते तापमान ने कृषि मौसम को बदल दिया है, जिससे बुवाई में देरी हुई है और गर्मी का तनाव जल्दी हुआ है, जिससे गेहूं की उपज और गुणवत्ता पर काफी असर पड़ा है।

मुख्य मुद्दे

- **गेहूं उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव**
  - o बुवाई में देरी: बढ़ते तापमान के कारण खरीफ का मौसम लंबा हो जाता है, जिससे गेहूं जैसी रबी फसलों की बुवाई में देरी होती है।
  - o फसल कटाई के दौरान गर्मी की लहरें: भारतीय मौसम विभाग ने फरवरी 2025 को 124 वर्षों में सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज किया है, जिसमें मार्च में उच्च तापमान की भविष्यवाणी की गई है, जिसका सीधा असर गेहूं की फसल पर पड़ रहा है।
  - o अनाज भरने की अवधि में कमी: अत्यधिक गर्मी के कारण फूल और पकने की प्रक्रिया में तेजी आती है, जिससे अनाज हल्का हो जाता है, स्टार्च की मात्रा कम हो जाती है और उपज कम हो जाती है।
  - o मिलिंग की गुणवत्ता में कमी: गर्मी के तनाव के कारण प्रोटीन अधिक होता है, लेकिन स्टार्च कम होता है, जिससे गेहूं कठोर हो जाता है और मिलिंग के लिए कम उपयुक्त होता है।
- **हिंद महासागर का गर्म होना और मानसून में परिवर्तनशीलता**
  - o त्वरित गर्मी: हिंद महासागर में तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे मानसून का पैटर्न प्रभावित हो रहा है।
  - o समुद्री गर्म लहरें: भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा किए गए एक अध्ययन में समुद्री गर्म लहरों के दिनों में दस गुना वृद्धि की भविष्यवाणी की गई है, जिससे अनियमित वर्षा होगी।
  - o विलंबित मानसून: मानसून चक्र में परिवर्तन से खरीफ की कटाई में देरी होती है, जिससे रबी फसल की बुवाई प्रभावित होती है।
- **आर्थिक और कृषि परिणाम**
  - o कम फसल पैदावार: 2024-2025 में, गेहूं की खरीद 26.6 मिलियन टन रही, जो 34.15 मिलियन टन के लक्ष्य से कम है।
  - o किसानों की आय में कमी: कम पैदावार से किसानों में वित्तीय संकट पैदा होता है, जिससे वे उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करने लगते हैं, जिससे मिट्टी की सेहत और खराब हो जाती है।
  - o निर्यात प्रतिबंध: मई 2022 में, भारत ने रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद वैश्विक कमी के कारण गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे खाद्य सुरक्षा की भेद्यता प्रदर्शित हुई।

अनुकूलन और शमन रणनीतियाँ

- **जलवायु-अनुकूल गेहूँ की किस्में**
  - o कम वृद्धि चक्र वाली गर्मी-प्रतिरोधी गेहूँ की किस्मों का विकास और संवर्धन।
  - o किसानों के लिए बेहतर बीजों तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करना।
- **नीतिगत हस्तक्षेप**
  - o बुवाई की अवधि में बदलाव: जल्दी गर्मी की लहरों की आशंका वाले क्षेत्रों में जल्दी बुवाई को प्रोत्साहित करना।

- o वित्तीय सहायता और फसल बीमा: फसल के नुकसान के लिए मुआवज़ा देना और बीमा योजनाओं का विस्तार करना।
- o संसाधन प्रबंधन: पैदावार को अनुकूलित करने के लिए उर्वरकों, कीट नियंत्रण और सिंचाई के प्रबंधन में सुधार करना।

- **तकनीकी और वैज्ञानिक समाधान**
  - o मौसम निगरानी प्रणाली: गर्मी की लहरों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत करना।
  - o किसान शिक्षा: जलवायु-स्मार्ट कृषि पद्धतियों पर किसानों को प्रशिक्षण देना।
  - o कुशल जल उपयोग: बढ़ते तापमान के तहत उत्पादन को बनाए रखने के लिए ड्रिप सिंचाई और जल संरक्षण तकनीकों को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष

- जलवायु परिवर्तन भारत के गेहूँ उत्पादन के लिए एक बड़ा खतरा है। बढ़ते तापमान, बदलते मानसून और बढ़ती गर्मी की लहरों के कारण गेहूँ की पैदावार और गुणवत्ता खराब हो रही है। नीति निर्माताओं को खाद्य सुरक्षा की रक्षा करने तथा दीर्घकाल तक गेहूं उत्पादन को बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, वित्तीय सहायता तथा तकनीकी समाधानों को मिलाकर एक बहुआयामी रणनीति अपनानी होगी।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: भारत के गेहूँ उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर चर्चा करें। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या अनुकूलन उपाय किए जा सकते हैं? (250 words)

GEO IAS
It's about quality

एक कार्यशील लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आवश्यक हैं। भारत में, मतदान प्रक्रिया, अभियान व्यय और राजनीति के अपराधीकरण से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए चुनावी सुधार आवश्यक हैं।

Why are electoral reforms necessary?

Since when have votes been registered solely through Electronic Voting Machines? Why have certain Opposition parties accused the EC of electoral roll manipulation? Should criminal cases of politicians standing for elections be given wide publicity?

EXPLAINER

Rangarajan R.

The story so far:

The Election Commission (EC) has invited political parties to discuss strengthening the election process. This is in wake of the allegations of manipulation of electoral rolls during the recently concluded assembly elections and issues raised with respect to duplicate Electoral Photo Identity Card (EPIC) numbers in different States.

What are the legal provisions?

Article 324 of the Constitution provides that the superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls for, and the conduct of, all elections to the Parliament and State legislature shall be vested in the EC. The preparation of electoral rolls is governed by the provisions of the Representation of the People Act, 1950 and related rules, including Registration of Electors Rules, 1960.

The voting process has undergone tectonic changes since the first general election in 1952. In the first two general elections of 1952 and 1957, a separate box was placed for each candidate with their election symbol. Voters had to drop a blank ballot paper into the box of the candidate whom they wanted to vote for. It is only from the third general election in 1962 that ballot papers with names and symbols of candidates was introduced. Subsequently, since the 2004 general elections to the Lok Sabha, Electronic Voting Machines (EVM) have been used in all constituencies. Since 2019, EVMs have been backed by 100% Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT) slips in all constituencies.

What are the issues?

There have been a series of issues raised in the past with respect to the voting and counting process. First, there were demands through a Public Interest Litigation (PIL) for reverting to paper ballot papers which was dismissed by the Supreme Court in April 2024. Second, the same PIL demanded 100% matching of VVPAT with EVM count, which at present is carried out for five machines per assembly constituency/segment. The Supreme court, while dismissing this demand as well, had directed that the burnt memory of microcontrollers of 5% of EVMs, which includes that of control units, ballot units, VVPATs, in every assembly segment can be checked and verified by a team of engineers of the EVM manufacturers in case of any suspicion of tampering. The exercise needs to be initiated via a written request from candidates who are placed second or third in a constituency, within seven days of the declaration of election results.

Third, there were allegations of manipulation of electoral rolls in the run up to the Maharashtra and Delhi Assembly elections. The Opposition parties alleged that large number of bogus/fake voters were added to the electoral roll to benefit the ruling party at the Centre. The fourth and current issue relates to identical EPIC numbers for voters belonging to different States like West Bengal, Gujarat, Haryana and Punjab. Opposition parties such as the Trinamool Congress allege that it vindicates their claim of bogus voters being included in the voters' list. The EC has explained that duplication may have arisen because of the earlier decentralised system for allotting EPIC numbers before shifting to the centralised database on the ERONET platform. It clarified that irrespective of the EPIC number, an elector can cast his/her vote only in their designated polling station in their State or Union Territory.

Apart from the above issues in the election process, there are significant issues related to the campaign process that have to be addressed. First, 'Star Campaigners' of most parties have been guilty of using inappropriate and abusive words against leaders of other political parties, appealing to caste/communal feelings of electors, and making unsubstantiated allegations. Second, candidates of all major political parties breach the election expenditure limit by a wide margin. Further, there are no limits on political party spending during elections. The Centre for Media Studies has estimated that the expenditure during the 2024 Lok Sabha elections was close to ₹1,00,000 crore by various political parties. Such inflated election expenditure fuels corruption resulting in a vicious cycle. Third, as per the report of the Association of Democratic Reforms, the issue of criminalisation of politics has almost reached its nadir with 251 (46%) of the 543 elected MPs in 2024, having criminal cases against them. Of them 170 (31%) face serious criminal charges including rape, murder, attempt to murder and kidnapping.

What are the required reforms?

Free and fair elections is part of the basic structure of our Constitution as declared by the Supreme Court in various cases.

With respect to the electoral process of voting and counting, the following reforms need to be considered and implemented. First, as regards the EVM and VVPAT related aspects, the sample size for the matching of EVM count and VVPAT slips should be decided in a scientific manner by dividing each State into large regions. In case of even a single error, VVPAT slips should be counted fully for the concerned region. This would instil statistically significant confidence in the counting process. Further, as recommended by the EC in 2016, in order to provide a degree of cover for voters at the booth level, 'totaliser' machines can be introduced that would aggregate votes in 14 EVMs before revealing the candidate-wise count. The candidates placed second or third should also utilise the direction of the Supreme Court to demand the verification of 5% of EVMs in each assembly segment in case of any suspected tampering. If any issue is identified, it should be suitably addressed and if there are none, it would put to rest the political speculation.

Second, to address the apprehension of inclusion of fake voters and duplicate EPIC cards, the process of linking citizens' Aadhaar number with EPIC cards may be considered after detailed discussions with all stakeholders and dispelling concerns around right to privacy. Meanwhile, the EC should remove any duplicate voter ID numbers in the electoral roll across States and ensure unique EPIC numbers.

Equally important, if not more, are the reforms needed in the campaign process. First, the EC should be authorised to revoke the 'Star Campaigner' status of a leader, in case of any serious violation of the Model Code of Conduct (MCC), thereby depriving the party candidates of expenditure relief for their campaigns. Under Paragraph 16A of the Symbols order, the EC has the power to suspend or withdraw the recognition of a recognised political party for its failure to observe MCC or follow lawful directions of the Commission. Strict action under this provision against bigger parties would have a salutary effect in ensuring adherence to the MCC. Second, with respect to election expenditure, the law must be amended to explicitly provide that 'financial assistance' by a political party to its candidate should also be within the limits of election expenditure prescribed for a candidate. There should also be a ceiling on expenditure by political parties. Third, the Supreme Court direction to candidates as well as political parties to issue declarations about criminal antecedents, at least three times before election, in a widely circulated newspaper in the locality and in electronic media, should be strictly enforced. This would enable a discerning voter in exercising a well-informed choice.

The EC and various political parties should engage in a meaningful discussion on all these aspects so that the campaign and electoral processes instil confidence in voters at large.

Rangarajan R is a former IAS officer and author of 'Polity Simplified'. He currently trains civil service aspirants at Officers IAS Academy. Views expressed are personal.

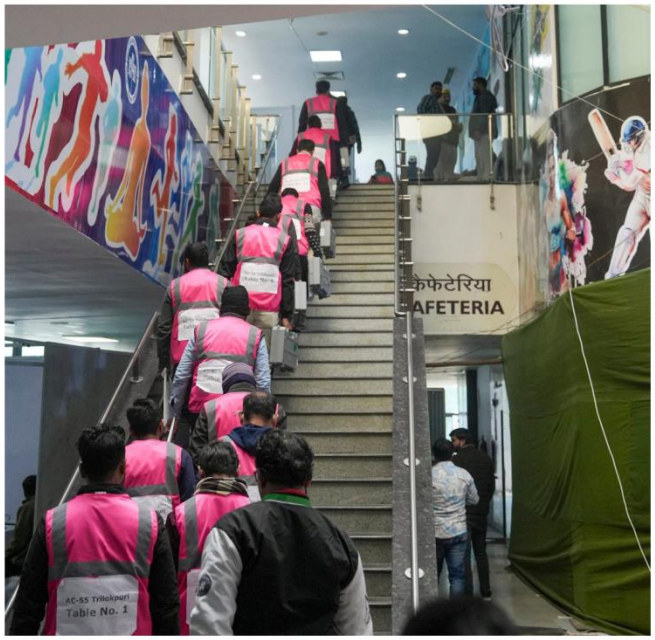

Need for a revamp: Poll officials carrying EVMs enter the Patparganj counting centre for the Delhi Assembly polls, in New Delhi, on February 8. PTI

THE GIST

- Article 324 of the Constitution provides that the superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls for, and the conduct of, all elections to the Parliament and State legislature shall be vested in the EC.
- Apart from the above issues in the election process, there are significant issues related to the campaign process that have to be addressed. First, 'Star Campaigners' of most parties have been guilty of using inappropriate and abusive words against leaders of other political parties, appealing to caste/communal feelings of electors, and making unsubstantiated allegations.
- As regards the EVM and VVPAT related aspects, the sample size for the matching of EVM count and VVPAT slips should be decided in a scientific manner by dividing each State into large regions. In case of even a single error, VVPAT slips should be counted fully for the concerned region. This would instil statistically significant confidence in the counting process.

- मतदाता सूची में हेराफेरी और डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र के आरोपों सहित हाल के विवादों ने चुनावों में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को उजागर किया है।

मुख्य कानूनी प्रावधान

- संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग (ईसी) को मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने का अधिकार देता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के साथ मतदाता पंजीकरण और मतदाता सूची को नियंत्रित करता है। 2004 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की शुरूआत और 2019 में वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) को शामिल करना मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता में सुधार की दिशा में उठाए गए कदम थे।

चुनावी प्रक्रियाओं में प्रमुख मुद्दे

- **मतदान और मतगणना संबंधी चिंताएँ**
  - अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने पेपर बैलेट पर वापस लौटने की माँग को खारिज कर दिया।
  - 100% वीवीपीएटी सत्यापन की याचिका को भी खारिज कर दिया गया, लेकिन अदालत ने संदिग्ध छेड़छाड़ के मामलों में 5% ईवीएम की जली हुई मेमोरी के सत्यापन की अनुमति दी।
  - महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची में हेराफेरी के आरोप, जिसमें फर्जी मतदाताओं के कारण सत्तारूढ़ पार्टी को लाभ पहुँचने का दावा किया गया।
  - पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा और पंजाब जैसे विभिन्न राज्यों में एक जैसे इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) नंबर दिखाई देने से डुप्लिकेट मतदाताओं के बारे में चिंताएँ बढ़ रही हैं।

अभियान संबंधी मुद्दे

- राजनीतिक नेता अक्सर अनुचित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जाति या सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काते हैं और असत्यापित आरोप लगाते हैं।
- चुनाव खर्च की सीमा नियमित रूप से पार हो जाती है, जिसमें पार्टी के खर्च की कोई सीमा नहीं होती। 2024 के लोकसभा चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अनुमानित ₹1,00,000 करोड़ खर्च किए गए।
- राजनीति का अपराधीकरण एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है, 2024 में 46% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं।

आवश्यक सुधार

- **मतदान और मतगणना सुधार**
- VVPAT सत्यापन के लिए नमूना आकार वैज्ञानिक रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए, विसंगतियों के मामले में पूर्ण सत्यापन के साथ।
- 'टोटलाइज़र' मशीनों को कई ईवीएम से वोट एकत्र करने के लिए पेश किया जाना चाहिए, ताकि पारदर्शिता में सुधार करते हुए मतदाता गोपनीयता बनाए रखी जा सके।
- चुनाव में दूसरे या तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमत 5% ईवीएम के सत्यापन का सक्रिय रूप से अनुरोध करना चाहिए।

मतदाता सूची और मतदाता पहचान सुधार

- गोपनीयता संबंधी चिंताओं को दूर करने के बाद आधार को ईपीआईसी कार्ड से जोड़ने पर विचार किया जाना चाहिए।
- चुनाव आयोग को दोहराव और धोखाधड़ी वाले मतदान को रोकने के लिए राज्यों में अद्वितीय ईपीआईसी नंबर सुनिश्चित करना चाहिए।

अभियान और राजनीतिक वित्तपोषण सुधार

- आदर्श आचार संहिता के गंभीर उल्लंघन के लिए चुनाव आयोग को 'स्टार प्रचारक' का दर्जा रद्द करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।
- चुनाव आयोग को प्रतीक आदेश के पैराग्राफ 16ए के तहत पार्टी की मान्यता निलंबित करने सहित कठोर दंड लागू करना चाहिए।
- राजनीतिक दलों से वित्तीय सहायता को उम्मीदवारों की व्यय सीमा में शामिल करने के लिए कानूनों में संशोधन किया जाना चाहिए।
- पार्टियों के चुनाव व्यय पर एक सीमा तय की जानी चाहिए।

राजनीति का अपराधीकरण

- उम्मीदवारों और पार्टियों को चुनाव से पहले तीन बार समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपराधिक रिकॉर्ड घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
- मतदाताओं को सूचित विकल्प बनाने के लिए उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में स्पष्ट जानकारी तक पहुँच होनी चाहिए।

निष्कर्ष

- भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास बहाल करने के लिए चुनावी सुधार आवश्यक हैं। मतदान प्रक्रियाओं को मजबूत करना, अभियान संबंधी कदाचार को कम करना और राजनीति के अपराधीकरण को संबोधित करना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करेगा। इन सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों को सार्थक चर्चा करनी चाहिए।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करें। चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए सुधार सुझाएँ। (250 words)

- फरवरी 2025 में भारत के थोक मूल्य सूचकांक (WPI) मुद्रास्फीति बढ़कर 2.38% हो गई, जो विनिर्मित उत्पादों और गैर-खाद्य प्राथमिक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण है। खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति के चार महीने के निचले स्तर पर पहुंचने और ईंधन और बिजली क्षेत्र में निरंतर अपस्फीति के बावजूद यह वृद्धि हुई है।

Manufactured items hasten Feb. WPI inflation to 2.38%

Prices of manufactured products rose to a two-year high of 2.86% in February; non-food primary inflation hastened to 4.84% in the reporting month as against 2.85% in the previous month

Ashokamithran T.
MUMBAI

Wholesale price inflation hastened to 2.38% as cost of manufactured food products, among others, increased in February, from 2.31% in the previous month, according to data from Ministry of Commerce and Industry.

Prices of manufactured products rose to a two-year high of 2.86% in the reporting month.

"Excluding food, core manufactured WPI inflation rose to 1.3% y-o-y from 1% in January. We think core WPI inflation may rise gradually over the coming months, reflecting the rise in international metal prices in February," said Aastha Gudwani, India Chief Economist at Barclays Research. Primary articles continued to dis-inflate for six consecutive months coming in at 2.81% in February 2025. Food price inflation was at a four-month low of 3.38% in February 2025. "Expectedly, the correction is now tapering," Ms. Gudwani wrote in the research note. Non-food primary inflation rose to 4.84% in the reporting month as against 2.85% in the previous month. The increase was however on account of a lower base, Ms. Gudwani wrote.

Fuel and power sector experienced a deflation of 0.71%, slowing from a fall in prices by 2.78% in January 2025. Price change in the sector has been in the negative territory for seven months.

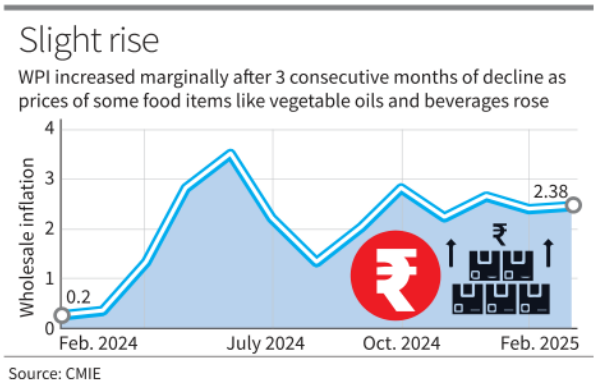

Source: CMIE

थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में मुख्य रुझान

विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति

- विनिर्मित उत्पादों की कीमतें फरवरी में **2.86%** के दो साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं।
  - मुख्य विनिर्मित थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति (खाद्य को छोड़कर) जनवरी में **1%** से बढ़कर **1.3%** हो गई।
  - विशेषज्ञों का अनुमान है कि अंतर्राष्ट्रीय धातु कीमतों में वृद्धि से प्रभावित मुख्य थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में धीरे-धीरे वृद्धि होगी।
- **प्राथमिक वस्तुएं और खाद्य मुद्रास्फीति**
  - प्राथमिक वस्तुओं में लगातार छठे महीने भी गिरावट जारी रही, जो **2.81%** पर आ गई।

- खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति घटकर **3.38%** हो गई, जो चार महीने का निचला स्तर है।
- खाद्य मुद्रास्फीति में सुधार धीमा हो रहा है, जो कीमतों में संभावित स्थिरता का संकेत देता है।

- **गैर-खाद्य प्राथमिक मुद्रास्फीति**
  - गैर-खाद्य प्राथमिक वस्तुओं की मुद्रास्फीति फरवरी में बढ़कर **4.84%** हो गई, जबकि जनवरी में यह **2.85%** थी।
  - यह वृद्धि कम आधार प्रभाव के कारण है, जो कीमतों में प्रतिशत वृद्धि को बढ़ाता है।

- **ईंधन और बिजली क्षेत्र में अपस्फीति**
  - इस क्षेत्र में **0.71%** की अपस्फीति देखी गई, जो जनवरी में **2.78%** की गिरावट से बेहतर है।
  - इस क्षेत्र में कीमतें लगातार सात महीनों से नकारात्मक क्षेत्र में बनी हुई हैं, जो ऊर्जा लागत पर निरंतर नीचे की ओर दबाव का संकेत देती हैं।

अर्थव्यवस्था के लिए निहितार्थ

- विनिर्माण क्षेत्र: निर्मित वस्तुओं की बढ़ती लागत आने वाले महीनों में उच्च खुदरा मुद्रास्फीति में योगदान दे सकती है।
- धातु की कीमतें: अंतरराष्ट्रीय धातु की कीमतों में अपेक्षित वृद्धि से कोर विनिर्माण में लागत दबाव और बढ़ सकता है।
- नीतिगत विचार: सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (**RBI**) को मूल्य स्थिरता और आर्थिक विकास से संबंधित नीतियों को तैयार करते समय इन मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों पर नज़र रखने की आवश्यकता हो सकती है।

निष्कर्ष

- फरवरी की **WPI** मुद्रास्फीति में **2.38%** की वृद्धि विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ते लागत दबाव को उजागर करती है, भले ही खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति कम हो रही हो। जबकि ईंधन और बिजली में अपस्फीति बनी हुई है, गैर-खाद्य प्राथमिक मुद्रास्फीति और मुख्य विनिर्माण कीमतों में बढ़ती प्रवृत्ति आने वाले महीनों में मुद्रास्फीति की उम्मीदों को प्रभावित कर सकती है।.

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: वायु प्रदूषण सौर ऊर्जा उत्पादन को कैसे प्रभावित करता है? नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए भारत की रणनीतियों पर चर्चा करें। (250 words)

A land where ambition grows minus an outbound ticket

Shashi Tharoor

is a fourth-term Member of Parliament (Congress), Lok Sabha, for Thiruvananthapuram, Chairman of the Parliamentary Standing Committee on External Affairs, and the Sahitya Akademi Award-winning author of 26 books, including 'Pax Indica: India and the World of the 21st Century' (2012)

The recent drama over the unceremonious repatriation of Indians who attempted illegally to enter the United States of America, and who ended up handcuffed and manacled in an American military aircraft that dumped them on the tarmac in Amritsar, raises a whole series of issues. Migration, after all, is not merely a policy issue. It is a human story, woven into our collective memories and dreams.

Immigration has long been an integral part of human history, shaping civilisations, economies, and societies across the globe. India, with its rich tradition of global engagement, has long seen its people traverse continents in pursuit of opportunity, new lives, better futures. Every year, millions of Indians embark on this journey, making India the country with the highest number of emigrants in the world. Today, Indians are no longer just workers abroad; they are leaders, shaping global industries. With Sundar Pichai at Google, Satya Nadella at Microsoft, and a host of others born and raised in India heading Fortune500 companies, Indian migrants drive innovation and economic power in the West. History proves that migration has always been a force multiplier, enriching both migrants and host nations. Yet, in an era of rising walls, both physical and political, migration faces unprecedented scrutiny.

A paradox that is painful

For decades, the lure of the American Dream has beckoned young Indians with the promise of economic opportunity, social mobility, and the prospect of a better future. While the IT engineers in Silicon Valley went on scholarships or work visas and stayed on, the Sikh cab drivers navigating the streets of New York may have found less conventional means of entry. But these illegal migrants are not fugitives but opportunity-seekers wanting a fair shot at prosperity. With remittances to India crossing $120 billion in 2023, migration fuels a cycle where families seek to replicate the success of relatives abroad. It is the vast expanse of opportunity in major U.S. cities, the promise of work under the radar, and the prospect of eventual amnesty (like so many before them) that draws them in. An estimated 7,25,000 undocumented Indian migrants – nearly one in four of all Indians in the U.S. – live and work clandestinely in the U.S.

There is a painful paradox at the heart of India's illegal migration story. We celebrate tech billionaires while youth unemployment soars, showcase gleaming infrastructure while millions struggle for dignified work. India's growth story features booming statistics, shrinking opportunities, and a rising economy still unable to assure its own people that their future lies at home.

The lure of foreign shores is sometimes about ambition, sometimes about survival. This has birthed a thriving network of unscrupulous agents weaving fantasies of western riches, convincing even people from India's most prosperous States to leave. Gujarat – a State championed as an economic success story, the launch-pad of the Prime Minister's rise – sees thousands risking everything to migrate. Punjab, too, is revered as India's breadbasket; it feeds the nation, yet its youth are leaving in droves. Rising unemployment, dwindling agricultural returns, and an insidious drug crisis have eroded hope, leaving many with little choice but to seek their fortunes abroad, legally or otherwise.

In their desperation, many Indians turn to shadowy networks, paying staggering sums to be smuggled across borders. What was once the path of young, single men now sees entire middle-class families – the bedrock of India's ambitions– risking everything for a fresh start abroad. The Gujarati family that froze to death trapped in a snowdrift on the Canadian-U.S. border in January 2022 was upper middle-class at home. Some of those who were sent back by the U.S. had paid a crore of rupees to get there. Who would have imagined that people with a crore of rupees would not thrive in India? Why is India, one of the world's fastest-growing economies, a rising geopolitical force, and a nation with unparalleled human capital, still unable to provide enough opportunities for its own people? Why has the pursuit of dignity, stability, and economic security led millions of Indians to distant shores, even where they are not welcome? These are uncomfortable questions – ones we can no longer ignore.

> The unceremonious repatriation of Indians must awaken those who govern the country – India must become a nation where migration is an option, not a necessity

More mirage than dream

There is also the question of what they find when they get there. The American Dream, once seen as a golden ticket, is increasingly a mirage. Many find themselves trapped in an endless cycle of uncertainty – living in fear of deportation, working in jobs that barely sustain them, struggling to integrate into societies that, at times, view them with racist suspicion. And for many who leave, the struggle does not end when they cross the border – it follows them, sometimes in the most tragic ways. We hear of migrants working endless hours in exploitative conditions, of families back home waiting for news that never comes. And now, for many, the journey merely ends in humiliating deportation.

The United States is well within its legal authority to return those who have entered its territory unlawfully. They have been doing so: the Biden administration deported 1,100 Indians in the last fiscal year. Since October 2020, nearly 1,70,000 Indian migrants have been detained by U.S. Customs and Border Protection while attempting to cross the border illegally, largely from Canada or Mexico; they are all subject to deportation. However, the manner in which this process is conducted has been dismaying. Deportation must be carried out with dignity and a respect for human rights. The recent images of shackled and handcuffed migrants being loaded onto military aircraft, suggesting more a criminal extradition of felons than an immigration enforcement measure, have understandably agitated Indians. Colombia and Mexico have rejected such treatment of their citizens, rightly arguing that deportation is an administrative process, not a punitive spectacle. Humiliating individuals to deter others serves no just purpose – it merely erodes dignity and distorts perceptions.

Issues to ponder over

We must ask: should a democracy treat another's citizens this way? Does border enforcement justify undermining the very values the deporting nation upholds? Diplomacy is not just policy but also a reflection of national character. While India does not, and should not, endorse illegal immigration, we cannot be silent spectators to the mistreatment of our citizens. A nation's stature is not just economic clout or international reach but the respect its passport commands. True global engagement is not just about alliances and trade deals; it is about setting an unwavering standard – wherever an Indian stands, their nation stands with them.

Another paradox: We hail the aspirational young Indian, but he prefers to fulfil his aspirations abroad. India must not be a place migrants are forced to return to, but one they want to return to. Those coming back are not just deportees but skilled, ambitious individuals whose aspirations can drive India's growth. We must make opportunities accessible to all, not concentrated among the privileged. Inclusive growth, innovation, and investments in infrastructure, education, and entrepreneurship must be national imperatives. More than just jobs, India must offer careers that inspire people to stay, build, and invest in their future here.

As the world builds walls, India must build bridges – to opportunity, prosperity, and a future where migration is an option, not a necessity. If India is to truly rise, it must become a nation where people do not feel compelled to leave, but empowered to stay. India must not just be the world's largest exporter of talent but a magnet for it – a place where ambition flourishes without an outbound ticket, where success is celebrated at home, and where prosperity is not a foreign fantasy but a reality shaped on our own soil.

Let us make India, once again, a land of hope. Not because the world is rejecting our people, but because, if we do the right things, they will have no need to look elsewhere.

The writer is grateful to Urjasvi Ahlawat for her assistance

GS Paper 01 भारतीय एवं विश्व भूगोल

UPSC Mains Practice Question: सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के बावजूद, भारत में अवैध प्रवास सहित प्रवास की दर बहुत अधिक है। इस विरोधाभास के पीछे के कारणों का विश्लेषण करें और इस मुद्दे को हल करने के उपाय सुझाएँ।

संदर्भ:

- प्रवास हमेशा से ही मानव सभ्यता का एक परिभाषित तत्व रहा है। यह दुनिया भर में समाजों, अर्थव्यवस्थाओं और सांस्कृतिक परिदृश्यों को आकार देता है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय प्रवासियों के निर्वासन के आसपास का हालिया विवाद एक जटिल और दर्दनाक वास्तविकता पर प्रकाश डालता है।
- जबकि भारत अपनी वैश्विक उपलब्धियों का जश्न मना रहा है, इसकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा कानूनी या अन्यथा कहीं और अवसरों की तलाश कर रहा है।
- अब भारतीय प्रवास के विरोधाभास, इसे चलाने वाले कारकों, प्रवासियों के सामने आने वाली चुनौतियों और एक ऐसे भविष्य के निर्माण पर राष्ट्रीय आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता का पता लगाना महत्वपूर्ण हो जाता है, जहाँ प्रवास एक आवश्यकता के बजाय एक विकल्प हो।

भारतीय प्रवासी: सफलता और संघर्ष

- भारत में दुनिया में सबसे अधिक संख्या में प्रवासी हैं।
- कई भारतीय विदेश में सफल हुए हैं, जिनमें सुंदर पिचाई (गूगल के सीईओ) और सत्य नडेला (माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ) जैसे नेता भारत की बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं।
- ये व्यक्ति एक ऐसी सफलता की कहानी का प्रतीक हैं, जिस पर भारत गर्व करता है। हालाँकि, भारतीय प्रवास की कहानी एक समान नहीं है।
- स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर हज़ारों अनिर्दिष्ट प्रवासी हैं, जिनमें से कई कनाडा या मैक्सिको के माध्यम से अक्सर अवैध मार्गों से संयुक्त राज्य अमेरिका की ख़तरनाक यात्राएँ करते हैं।
- टेक उद्यमियों और कुशल पेशेवरों के विपरीत, ये प्रवासी युद्ध या उत्पीड़न से भाग नहीं रहे हैं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता की तलाश कर रहे हैं, जिसके बारे में उनका मानना है कि उनका गृह देश उन्हें यह सुरक्षा और स्थिरता प्रदान नहीं कर सकता।
- उनकी दुर्दशा एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है: तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था से जुड़े होने के बावजूद इतने सारे भारतीय विदेश में अनिश्चित भविष्य के लिए सब कुछ जोखिम में डालने की ज़रूरत क्यों महसूस करते हैं?

भारत के आर्थिक विकास और प्रवास का विरोधाभास

- भारत के प्रवास संकट के मूल में एक दर्दनाक विरोधाभास है। भारत प्रभावशाली आर्थिक विकास का दावा करता है, फिर भी बढ़ती युवा बेरोज़गारी और आर्थिक असमानता लोगों को दूर कर रही है।

- जबकि शहरी केंद्र विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचे का प्रदर्शन करते हैं, कई नागरिक अभी भी सम्मानजनक काम के लिए संघर्ष करते हैं।
- आर्थिक रूप से समृद्ध माने जाने वाले गुजरात और पंजाब जैसे राज्यों में अवैध प्रवास की दर बहुत अधिक है।
- कनाडा-अमेरिका सीमा पर दुखद रूप से ठंड से मरने वाले गुजराती परिवार जैसे संपन्न परिवारों की हताशा बताती है कि समस्या केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि आकांक्षा और सामाजिक गतिशीलता की भी है।

यह विरोधाभास एक असहज प्रश्न उठाता है:

- यदि भारत वास्तव में प्रगति कर रहा है, तो इसके इतने सारे लोग क्यों जाने के लिए मजबूर महसूस करते हैं?

प्रवासन को बढ़ावा देने वाले कारक

- **बढ़ती अर्थव्यवस्था, घटते अवसर**
  - o पहली नज़र में, भारत की अर्थव्यवस्था फलती-फूलती नज़र आती है।
  - o देश की जीडीपी वृद्धि दर कई विकसित देशों से ज़्यादा है, मध्यम वर्ग बढ़ रहा है और डिजिटल अर्थव्यवस्था तेज़ी से फैल रही है।
  - o यह दुनिया के कुछ सबसे मूल्यवान स्टार्टअप, एक शक्तिशाली आईटी क्षेत्र और वैश्विक विनिर्माण में बढ़ती उपस्थिति का घर है।
  - o फिर भी, इन आँकड़ों के पीछे एक कठोर वास्तविकता छिपी हुई है: आर्थिक विकास व्यापक, समावेशी अवसरों में तब्दील नहीं हुआ है।
  - o भारत के मजबूत आर्थिक संकेतकों के बावजूद, रोज़गार सृजन हर साल कार्यबल में प्रवेश करने वाले लाखों युवा भारतीयों के साथ तालमेल नहीं रख पाया है।

  मध्य-वर्ग का पलायन: क्यों अमीर लोग भी विदेश जा रहे हैं
  - o परंपरागत रूप से, पलायन आर्थिक आवश्यकता से प्रेरित था, जिसमें गरीब व्यक्ति अपने परिवारों का भरण-पोषण करने के लिए विदेश में कम-कुशल नौकरियों की तलाश करते थे।
  - o हालाँकि, हाल के वर्षों में, एक आश्चर्यजनक प्रवृत्ति सामने आई है, उच्च-मध्यम वर्ग के परिवार और यहाँ तक कि धनी व्यक्ति भी पलायन करना चुन रहे हैं।
  - o गुजरात और पंजाब जैसे राज्य, जिन्हें अक्सर आर्थिक सफलता की कहानियों के रूप में उद्धृत किया जाता है, हर साल हज़ारों लोग पलायन करते हैं।
  - o कई मध्यम-वर्गीय परिवार न केवल बेहतर वेतन के लिए बल्कि बेहतर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए विदेश जाते हैं।
  - o कई माता-पिता विदेशी शिक्षा को अपने बच्चों के लिए बेहतर नौकरी की संभावनाओं और बेहतर जीवन स्तर के प्रवेश द्वार के रूप में देखते हैं।
  - o जबकि भारत की स्टार्टअप संस्कृति फल-फूल रही है, नौकरशाही बाधाएँ, असंगत नियम और भ्रष्टाचार व्यवसायों के लिए कुशलता से विस्तार करना मुश्किल बनाते हैं।
- **समावेशी विकास की विफलता**
  - o भारत का पलायन विरोधाभास अंततः समावेशी विकास की विफलता है।
  - o जबकि देश अपनी आर्थिक प्रगति का जश्न मना रहा है, धन और अवसर विशिष्ट उद्योगों और समाज के कुछ वर्गों के बीच केंद्रित हैं।
  - o भारत के तेजी से शहरीकरण ने महानगरों में विकास को बढ़ावा दिया है, लेकिन ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्र रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के मामले में पिछड़े हुए हैं।

o इसके अतिरिक्त, कृषि जैसे क्षेत्र, जो अभी भी भारत के कार्यबल के एक बड़े हिस्से को रोजगार देते हैं, उत्पादकता और लाभप्रदता में गिरावट का सामना कर रहे हैं।
o कई किसानों के बच्चों को कृषि में कोई भविष्य नहीं दिखता और वे आर्थिक कठिनाई से बचने के साधन के रूप में पलायन की ओर देखते हैं।
o उदाहरण के लिए, पंजाब में नशीली दवाओं का संकट आंशिक रूप से खेती में घटते अवसरों के कारण युवाओं के मोहभंग से जुड़ा हुआ है।

अमेरिकी सपने का भ्रम

- संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे लंबे समय से अवसरों की भूमि के रूप में देखा जाता है, प्रवासियों, विशेष रूप से अनिर्दिष्ट लोगों के लिए एक कठिन स्थान बन गया है।
- अवैध रूप से अमेरिका पहुंचने वाले कई भारतीय खुद को कम वेतन वाली नौकरियों में फंसा हुआ पाते हैं, और लगातार निर्वासन के डर में रहते हैं।
- अमेरिकी सपना, जिसे कभी सुनहरा टिकट माना जाता था, अक्सर ऐसे समाज में अस्तित्व के लिए अंतहीन संघर्ष में बदल जाता है जो हमेशा बाहरी लोगों का स्वागत नहीं करता है।
- हाल ही में हुए निर्वासन अवैध प्रवास की कठोर वास्तविकता को उजागर करते हैं।
- जबकि अमेरिका के पास अनिर्दिष्ट व्यक्तियों को निर्वासित करने का कानूनी अधिकार है, लेकिन जिस तरह से यह किया जाता है, प्रवासियों को बेड़ियों और हथकड़ी लगाना, मानवीय गरिमा पर सवाल उठाता है।
- कोलंबिया और मैक्सिको जैसे अन्य देशों ने अपने नागरिकों के साथ इस तरह के व्यवहार की निंदा की है, यह मानते हुए कि निर्वासन एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, न कि आपराधिक सजा।
- भारत को भी अपने लोगों के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ़ कड़ा रुख अपनाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके नागरिकों के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाए।

आगे का रास्ता: बदलाव की आवश्यकता; घर पर अवसर पैदा करना

- **नौकरी सृजन और आर्थिक सुधार**
  o भारत को ऐसी नीतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो सार्थक रोजगार पैदा करें, खास तौर पर युवाओं के लिए।
  o अर्थव्यवस्था के बढ़ने के साथ-साथ रोजगार के अवसर बढ़ती आबादी के साथ तालमेल नहीं रख पाए हैं।
  o विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और सेवाओं जैसे उद्योगों में निवेश कार्यबल को अवशोषित करने में मदद कर सकता है।
- **शिक्षा और कौशल विकास में सुधार**
  o कई भारतीय प्रवासी उच्च शिक्षा योग्यता होने के बावजूद विदेशों में कम वेतन वाली नौकरियां करते हैं।
  o भारत की शिक्षा प्रणाली को उद्योग की मांगों के साथ संरेखित करने और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है जो युवाओं को आज के नौकरी बाजार के लिए प्रासंगिक कौशल से लैस करे।
- **बुनियादी ढांचे और उद्यमिता को मजबूत करना**
  o अगर भारत अपनी प्रतिभा को बनाए रखना चाहता है, तो उसे उद्यमिता और नवाचार को आसान बनाना होगा। कई भारतीय जो विदेश में सफल होते हैं, वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें विकास के लिए बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र मिलते हैं।
  o स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना, नौकरशाही बाधाओं को कम करना और वित्तीय सहायता प्रदान करना एक ऐसा माहौल बना सकता है जहाँ युवा भारतीय घर पर ही कामयाब हो सकें।

निष्कर्ष

- भारत की प्रगति का सही मापदंड केवल उसकी आर्थिक वृद्धि नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपनी प्रतिभा को बनाए रखने और अपने सभी नागरिकों को अवसर प्रदान करने की उसकी क्षमता होनी चाहिए।
- प्रवास एक विकल्प होना चाहिए, न कि हताशा से प्रेरित मजबूरी।

- भारत को प्रतिभाओं का निर्यात करने वाले देश से बदलकर उसे आकर्षित करने और उसका पोषण करने वाले देश में बदलना होगा।
- उभरता हुआ भारत एक ऐसा स्थान होना चाहिए, जहाँ महत्वाकांक्षा बिना किसी आउटबाउंड टिकट की आवश्यकता के पूरी हो, जहाँ सफलता की कहानियाँ सिर्फ़ सिलिकॉन वैली में ही नहीं बल्कि भारतीय शहरों और गाँवों में भी लिखी जाएँ।

GEO IAS
It's about quality